(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में इस्पात की वर्तमान उत्पादन लागत में कोई कमी किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या विदेशी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्वदेशी इस्पात की बिक्री करना अलाभप्रद है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई उचित उपाय किए हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) से (ग) अन्य देशों में इस्पात के उत्पादन की लागत के संबंध में प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। इस्पात के विभिन्न उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय लागत, प्रतिस्पर्धात्मकता कई घटकों जिनमें गुणवत्ता, भाड़ा, लेवी और कर आदि शामिल हैं, जो विभिन्न देशों में अलग-अलग हैं, पर निर्भर करती है।

तथापि, औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो (सी०आई०सी०पी०) ने हाल ही में इस्पात लागत अध्ययन के संबंध में एक दौरा रिपोर्ट प्रस्तुत की है। बी०आई०सी०पी० की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया और जापान की तुलना में भारत में परिसज्जित इस्पात की कारखाना बाह्य उत्पादन लागत तथा अमरीका और यूनाइटेड किंगडम की तुलना में भारत में विक्रय इस्पात की कारखाना बाह्य उत्पादन लागत नीचे दर्शाई गई है:—

1. भारत बनाम कोरिया और जापान वर्ष (1994-95)

देश	(अमरीकी डालर में लागत प्रति टन)	अभ्युक्ति
1	2	3
भारत		
(सेल: बोकारो)	411.65	
(सेल: भिलाई)	265.50	यह तुलना 1994-95 के लिए परिसज्जित इस्पात से संबंधित है।
कोरिया		
(पोहांग, पास्को)	569.77	
जापान		
(निप्पित्सु, नित्पोन)	591.13	

2. भारत बनाम यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका

देश	वर्ष (1994-95) (अमरीकी डालर में लागत प्रति टन)	अभ्युक्ति
भारत (सेल)	410	यह तुलना 1994 में विक्रेय इस्पात से संबंधित है।
संयुक्त राज्य अमेरिका	500	
यूनाइटेड किंगडम	423	

कुछ उपाय जिनसे मौजूदा उत्पादन लागत कम की जा सकती है, में शामिल है—क्षमता उपयोगिता बढ़ाना, उत्पादकता में सुधार करना, ऊर्जा संरक्षण उपाय करना, प्रभावी अनुरक्षण के जरिए उपस्करों की उपलब्धता में सुधार करना, उत्पाद मिश्र में सुधार करना, मूल्य वर्धित मदें बनाना और ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करना, कोक, ऊर्जा, भण्डार और हिस्से-पुर्जे आदि जैसे आदानों की खपत में कमी करना।

'सेल' के बोकारो, राउरकेला और दुर्गापुर स्थित संयंत्रों में इस समय चल रहे आधुनिकीकरण कार्यक्रमों का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन लागत में कमी करना है।

(घ) से (च) इस्पात के निर्यात की लाभप्रदता विभिन्न घटकों जैसे अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में मांग, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, निर्यात लाभ आदि पर निर्भर करती है। चूंकि वर्तमान नीति के अनुसार इस्पात का निर्यात निर्बाध रूप से करने की अनुमति है, इसलिए इस्पात का निर्यात करने का निर्णय उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा अपने आर्थिक दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए स्वयं लिया जाता है।

Clearance of proposals pending before FIPB

3336. **DR. D. VENKATESHWAR RAO**: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether as on date more than 170 proposals from foreign investors are pending before the FIPB;

(b) whether revamped FIPB had urged to set up and approve the priority projects;

(c) if so, by what time the FIPB is likely to clear these projects; and

(d) the reasons for the delay?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) Yes, Sir.

(b) The revamped Foreign Investment Promotion Board in its meetings is already considering foreign investment proposals and making apropriate recommendations on such proposals.

(c) and (d) Receipt of applications for consideration of FIPB and their disposal is a continuous process. The proposals are generally cleared within a period of 6 weeks.

World Bank loan for expansion of CIL projects in Madhya Pradesh

3337. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that World Bank has provided loan to CIL for expansion projects and replacement of heavy earth moving machinery in existing coal mines/projects in the State of Madhya Pradesh;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the projects have been identified for expansion in the State with the help of World Bank loan; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) Coal India Ltd. (CIL), have proposed a loan from the World Bank for a project entitled "Coal Sector Rehabilitation Project". The project *inter-alia* proposes to seek funds for heavy earth moving machinery etc. for expansion of mines in Madhya Pradesh.

Removal of infrastructural bottlenecks

3338. SHRI RAMDAS AGARWAL: SHRI SATISH AGARWAL:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government plan to remove infrastructural bottlenecks for exports to achieve exports worth US $100 billion by the end of the Ninth Plan period as reported in the Indian Express, New Delhi dated 14th August, 1996;

(b) the suggestions/decisions taken at the 16th Board of Trade meeting held recently in New Delhi to achieve a minimum export growth of 25 per cent by India, annually; and

(c) whether Government have till date taken any decision at the said meeting on FICCI's suggestions for greater financial support for export sectors such as gems and jewellery and textiles which are not constrained by infrastructural bottlenecks?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) to (c) Government is engaged in the continuous upgradation of export infrastructure. The Ministry of Commerce acts in co-ordination with the other Ministries, Departments and agencies for the purpose. Standing Committees on Promotion of Exports (SCOPE) in respect of air cargo (SCOPE-AIR) and sea borne cargo (SCOPE-SHIPPING) are functioning in the Ministry. These help to resolve constraints encountered in export transportation and to advise on long term strengthening of infrastructure. The Ministry of Surface Transport is upgrading the port infrastructure. Inland Container Depots (ICDs) and Container Freight Stations (CFSs) are being established in various parts of the country to facilitate container transportation of goods and intermodal conveyance. An Inter-Ministrial Committee accords